त्रिपुरा राज्य और अन्य

बनाम

के. के. रॉय

12 दिसंबर, 2003

[मुख्य न्यायाधिपति वी. एन. खरे, और न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा]

सेवा कानूनः

पदोन्नति-सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति -पदोन्नति के अवसर- एकल पद संवर्ग के लिए सरकारी कर्मचारी को एकल पद संवर्ग में नियुक्त किया जाता है, जिसके पास कोई पदोन्नति के अवसर नहीं होते हैं- धारित की वैधता: आयोजित किया गया - राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर पैदा करने चाहिए थे-ऐसे कर्मचारी 12 वर्ष पूरा होने के बाद वेतन का उच्च पैमाना और दूसरा 24 वर्ष पूरा होने पर हकदार हैं यदि इस बीच में पदोन्नत नहीं किया जाता है - भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14, 16

प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के प्रतिष्ठान में विधि अधिकारी-सह-ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था। कैडर में केवल एक पद था, जिसमें पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं था। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को कम से कम दो पदोन्नति के अवसर प्रदान करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे अनुमति दे दी गई।इसलिए याचिका दायर की गई है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक 'राज्य' होने के नाते अपीलार्थी को पदोन्नति के अवसर पैदा करने चाहिए थे भारत के संविधान के अनुच्छेद

14 और 16 में उल्लिखित अपने संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी के लिए। अपने संवैधानिक दायित्वों के बावजूद राज्य यह रुख नहीं अपना सकता कि प्रतिवादी ने प्रस्ताव के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है यह अच्छी तरह से जानते हुए कि नियुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, वह नियुक्ति से पीछे नहीं हट सकता। यह ऐसा मामला नहीं है जहां राज्य के संवैधानिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए विरोध के सिद्धांत या छूट के अधिकार को लागू किया जाना चाहिए। यह विवादित नहीं है कि भारत के अन्य राज्यों ने वेतन आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आश्वस्त करियर पदोन्नति की योजना शुरू की, जिसके तहत किसी पद पर आसीन व्यक्ति को 12 साल की अवधि के भीतर पदोन्नत नहीं किया जाता है। तो उसे एक उच्चतर पद प्रदान किया जाता है और दूसरा 24 वर्ष पूरे होने पर, यदि इस बीच पदोन्नति के रास्ते मौजूद होने के बावजूद उसे पदोन्नत नहीं किया गया हो। [784-ई-एच; 785-ए)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बनाम के. जी. एस. भट्ट, [1989। 4 एस. सी. सी. 635 और डॉ. सुश्री ओ. जेड. हुसैन बनाम भारत संघ, [1990] सप। एससीसी 688 , पर भरोसा किया।

1.2. यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी को 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अगले उच्च वेतनमान में दो पदोन्नति दी जाए। (785-ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6253/1998

(डब्ल्यू. ए. सं. 10/ 1997 में गुवाहाटी में असम उच्च न्यायालय के दिनांकित 7.4.1997 के निर्णय और आदेश से।)

अपीलार्थियों के लिए नवीन प्रकाश, गोपाल सिंह के लिए अनुराग शर्मा।

प्रतिवादी के लिए एस. वी. देशपांडे।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा,

त्रिपुरा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद, प्रतिवादी को त्रिपुरा सरकार के सहकारिता निदेशालय में विधि अधिकारी-सह-ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था। एक ही संवर्ग में केवल एक पद था और इसके लिए पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने एक अभ्यावेदन दायर किया कि उनके एक या दो पद का उन्नयन किया जाए। उसे पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं। उनके द्वारा किए गए कई अभ्यावेदनों पर अपीलकर्ताओं द्वारा विचार नहीं किए जाने के बाद, प्रतिवादी ने यहां एक रिट याचिका दायर की जिसमें अपीलार्थी को कम से कम दो पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश देने की मांग की गई।

प्रत्यर्थी के उक्त तर्क को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसके विवादित निर्णय के कारण अपीलार्थी को निर्देश दिया गया कि वह अपीलार्थी को तीन श्रेणी प्रदान करके 'श्रेणीबद्ध पैमाना' प्रदान करे, जिसमें प्रारंभिक श्रेणी III है जो विधि अधिकारी-सह-ड्राफ्ट्समैन का पद है और उसके बाद श्रेणी II और श्रेणी I त्रिपुरा न्यायिक सेवा का अधिकारी है। इसे आगे निर्देशित किया गया थाः

"ग्रेड II विधि अधिकारी-सह-ड्राफ्ट्समैन के वेतन का पैमाना त्रिपुरा न्यायिक सेवा के ग्रेड-II अधिकारी के समान होगा । ग्रेड-I विधि अधिकारी-सह-ड्राफ्ट्समैन के वेतन का पैमाना होगा त्रिपुरा न्यायिक के ग्रेड-I अधिकारी के वेतनमान के बराबर सेवा।"

उक्त निर्देश पर सवाल उठाते हुए, अपीलार्थी हमारे सामने हैं।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश जारी करने में गलती की। विद्वान वकील यह आग्रह

करेंगे कि प्रतिवादी को त्रिपुरा न्यायिक सेवा के ग्रेड I अधिकारी का वेतनमान प्राप्त करने का अधिकार तो दूर किसी उच्च पद पर पदोन्नत होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विद्वान वकील का तर्क है कि उच्च न्यायालय का ऐसा निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है। हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उक्त आदेश का समर्थन किया है।

निर्विवाद रूप से विधि अधिकारी-सह-ड्राफ्ट्समैन का पद एकल संवर्ग है।यह भी निर्विवाद है कि इसके लिए कोई प्रचार मार्ग मौजूद नहीं है। प्रत्यर्थी के पास मास्टर डिग्री के साथ-साथ कानून की डिग्री भी है। उन्हें वर्ष 1982 में नियुक्त किया गया था। यदि अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो प्रत्यर्थी को उसके पूरे कार्यकाल में पदोन्नत किए बिना छोड़ दिया जाएगा। लगभग एक समान स्थिति में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य बनाम के. जी. एस. भट्ट और अन्य, [1989] 4 एस. सी. सी. 635 में न्यायालय ने कहाः

"...यह अक्सर कहा जाता है और वास्तव में, चतुराई से, एक संगठन, सार्वजनिक या निजी, 'किसी को काम पर नहीं रखता' बल्कि एक पूरे व्यक्ति को काम पर रखता है या नियुक्त करता है। व्यक्ति को किसी संगठन द्वारा न केवल नौकरी के लिए, बल्कि पूरे कैरियर के लिए भर्ती किया जाता है , इसलिए, किसी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह इसकी सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्त उद्यम प्रणाली. उन्नति का अवसर किसी भी संगठन की प्रगति के लिए एक आवश्यकता है। यह कार्मिक विकास के लिए भी एक प्रोत्साहन है। (देखें: कार्मिक के सिद्धांत)

फ़िलपो एडविन द्वारा प्रबंधन, चौथा संस्करण, पृ. 246). प्रत्येक प्रबंधन को होनहार कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए यथार्थवादी अवसर प्रदान करने चाहिए। "जो

संगठन पदोन्नति के लिए एक संतोषजनक प्रक्रिया विकसित करने में विफल रहता है, उसे गैर-प्रबंधकीय कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षकों दोनों के बीच प्रशासनिक लागत, कर्मियों के गलत आवंटन, कम मनोबल और अप्रभावी प्रदर्शन के मामले में गंभीर जुर्माना देना पड़ता है।" (देखें: कार्मिक संचालन डॉ. उदय पारीक द्वारा, पृ. 277). कोई आधुनिक प्रबंधन नहीं हो सकता, कैरियर योजना, जनशक्ति विकास, प्रबंधन विकास इत्यादि तो दूर की बात है, जो पदोन्नति की प्रणाली से संबंधित न हो..."

यह मामला डॉ. सुश्री ओ. जेड. हुसैन बनाम में फिर से विचार के लिए आया। भारत संघ, [1990] पूरक एस. सी. सी. 688 जिसमें इस न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चित शर्त के कानून निर्धारित करते हुए कहाः

"...पदोन्नति इस प्रकार सेवा की एक सामान्य घटना है। इसका भी कोई औचित्य नहीं है कि अन्य मंत्रालयों में समान रूप से तैनात अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, जबकि स्वास्थ्य महानिदेशक की स्थापना में गैर-चिकित्सा 'ए' समूह के वैज्ञानिकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। सेवाओं को ऐसे लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य में, यह आवश्यक है कि एक कुशल सार्वजनिक सेवा होनी चाहिए और इसलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दायित्व होना चाहिए कि वह परिषद और उसके सदस्यों के अभ्यावेदन पर ध्यान दे और इस श्रेणी के अधिकारियों के लिए पदोन्नति का अवसर प्रदान करे। ..."

यह ऐसा मामला नहीं है जहां पदोन्नति के लिए कोई अवसर मौजूद था। यह ऐसा भी मामला नहीं है जिसमें राज्य ने प्रचार नीति में संशोधन करने का इरादा किया हो। संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य होने के नाते अपीलार्थी को पदोन्नति के अवसर पैदा करने चाहिए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में उल्लिखित अपने संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी के लिए। अपने

संवैधानिक दायित्वों के बावजूद, राज्य यह रुख नहीं अपना सकता है कि चूंकि प्रतिवादी ने नियुक्ति के प्रस्ताव के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से जानते हुए स्वीकार कर लिया है कि पदोन्नति नियुक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह उससे वापस नहीं जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें राज्य के संवैधानिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए रोक या छूट के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। यह विवादित नहीं है कि भारत/भारत संघ के अन्य राज्यों ने वेतन आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आश्वस्त करियर पदोन्नति की योजना शुरू की, जिसके तहत किसी पद पर आसीन व्यक्ति को 12 साल की अवधि के भीतर पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो उसे एक उच्च वेतनमान और 24 वर्ष पूरे होने पर दूसरा वेतनमान दिया गया, यदि इस बीच उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था प्रचार के रास्ते मौजूद होने के बावजूद। जब पूछताछ की जाती है, तो विद्वान अपीलार्थी की ओर से पेश वकील यह भी नहीं बता सके कि त्रिपुरा राज्य ने ऐसी योजना शुरू की है। हम आश्चर्य करते हैं कि भारत के अन्य राज्यों की तरह अपीलार्थी द्वारा ऐसी योजना क्यों शुरू नहीं की गई और ऐसा करने में क्या बाधा थी।

पदोन्नति सेवा की एक शर्त है और इसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यहाँ पहले निर्दिष्ट निर्णयों में इंगित किया गया था, यह उम्मीद की गई थी कि अपीलार्थी को उक्त सिद्धांत का पालन करना चाहिए था।

इस प्रकार, हमारी राय है कि यहाँ उत्तरदाता कम से कम वह दो उच्च श्रेणी प्रदान करने का हकदार है, एक सेवा में शामिल होने की तारीख से 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर और दूसरा 24 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर।

हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सही है। अपने निवेदन में कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी

अधिकारिता का प्रयोग करते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट जारी नहीं कर सकता था, जिसमें अपीलार्थी को राज्य की न्यायिक सेवा के ग्रेड II या ग्रेड I के बराबर वेतन देने का निर्देश दिया गया था।

उपर्युक्त कारणों से, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी को उसकी 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अगले उच्च वेतनमान में दो पदोन्नति का भुगतान किया जाए। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील निस्तारित की जाती है। कोई लागत नहीं.

वी. एस.एस

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।